

राज्यक़र्मा
अतारांकित प्रश्नीसंख्याण्2042
11 मई, 2016 को उत्तर के लिए

तैयार इस्पात का उपभोग और आयात

2042. श्री ए. यू. सिंह दिवः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या गत वर्ष तैयार इस्पात के उपभोग और आयात में वृद्धि हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने देश में सस्ते इस्पात उत्पादों के पाटन का संज्ञान लिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या सस्ते विदेशी इस्पात के विपरीत घरेलू उद्योगों के संरक्षण हेतु रक्षोपाय किए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (घ) क्या सरकार ने इस्पात उद्योग के विकास को आगे बढ़ाने के लिए कोई उपाय किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इस्पात और खान राज्य ब मंत्री

(श्री विष्णुय देव साय)

जी हां । गत वर्ष के दौरान पूर्ण फिनिशड इस्पात की खपत और आयात में वृद्धि हुई है : (क), जैसा कि ब्यौधरा नीचे दिया गया है :-

पूर्ण फिनिशड इस्पात (एमटी में)		
वर्ष	खपत	आयात
2015-16*	80.45	11.71
2014-15	76.99	9.32
वृद्धि %	4.5	25.7
स्रोत: जेपीसी * अनंतिम		

) से (ख)घः इस्पात नियंत्रण मुक्त क्षेत्र होने के नाते सरकार की भूमिका देश में इस्पात उद्योग के विकास के लिए एक सुविधा दाता के रूप में सीमित होती है। अतएव, इस्पात की विभिन्न श्रेणियों के उत्पाद निर्यात, आयात इत्यादि से संबंधित निर्णय विभिन्न घटकों यथा घरेलू बाजार में इस्पात की विभिन्न मदों की मांग, मुद्रा की कीमत में उतार चढ़ाव, आयात नियंत्रण इत्यादि के आधार पर अलगअलग इस्पात विनिर्माताओं के एक मात्र निर्णय पर निर्भर करते हैं। घरेलू इस्पात-उद्योग में विकास और सुरक्षा को सुनिश्चित करने तथा सस्ते आयातों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :-

- (i) यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल गुणवत्ता युक्त इस्पात का उत्पादन या आयात हो सरकार ने इस्पात और इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2012, दिनांक 12.03.2012 तथा इस्पात और इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता, नियंत्रण) आदेश, 2015, दिनांक 15.12.2015 अधिसूचित किए गए हैं।
- (ii) घरेलू इस्पात उद्योग के लिए कोयला और लौह अयस्क की उपलब्धता बढ़ाने के लिए-
- (क) कोयला ब्लाइक के आवंटन को सरल बनाने के लिए दिनांक 30.03.2015 को 'कोल माईन्स (स्पेलशल प्रोविजंस) एमेंडमेंट एक्ट 2015' अधिसूचित किया गया है।
- (ख) खनन पट्टे के आवंटन को सरल एवं कारगर बनाने के लिए दिनांक 27.03.2015 को 'खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015' अधिसूचित किया गया है।
- (iii) केन्द्रीय बजट 2015-16 में फ्लैट और नॉन-फ्लैट दोनों इस्पात पर बेसिक सीमा शुल्क की उच्चांतम दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत की गई है।
- (iv) इनगॉट्स और बिलेट्स, अलॉय स्टील (फ्लैट एवं लांग), स्टेनलैस स्टीमल (लांग) और नान-अलॉय लांग उत्पाद पर आयात शुल्क 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत किया गया तथा नान अलॉय और अन्य अलॉय फ्लैट उत्पादों पर यह शुल्क 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया गया है। अगस्त 2015 में पुनः संशोधित करके आयात शुल्क फ्लैट स्टील पर 10 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत, लांग स्टील पर 7.5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत और सेमी फिनिश स्टील पर 7.5 से 10 प्रतिशत किया गया है।
- (v) नवम्बर 2014 में रिबर्स का आयात केवल 'इस्पात उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण आदेश 2012' के अनुसार सुनिश्चित किया गया था, ताकि बोरन युक्त रिबर्स के सस्ते आयातों को रोका जा सके।
- (vi) सरकार ने जून, 2015 में स्टेनलैस स्टील के कतिपय किस्मों के हॉट रोलड फ्लैट उत्पादों के चीन (\$ 309 प्रति टन), कोरिया (\$ 180 प्रति टन) और मलेशिया (\$ 316 प्रति टन) से आयातों पर 5 वर्षों के लिए एंटी डम्पिंग ड्यूटी लगाई गई है।
- (vii) सरकार ने मार्च, 2016 में 600 एमएम या इससे अधिक की चौड़ाई वाले क्वाटयलों में नान अलॉय और अन्य अलॉय स्टील के हॉट रोलड फ्लैट उत्पादों पर 20 प्रतिशत का सुरक्षोपाय शुल्क लगाया है।
- (viii) दिनांक 05.02.2016 की अधिसूचना के जरिये 173 इस्पात उत्पादों पर न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) की शर्त लगाई गई है। इस अधिसूचना के तहत शामिल की गई मर्चों का इस देश में आयात अधिसूचित मूल्य से कम पर करने की अनुमति नहीं होगी।
- (ix) इस्पात क्षेत्र में दबाव को कम करने के लिए आरबीआई ने जुलाई, 2015 में 5:25 स्कीयम लागू की है जिसके द्वारा अवसरचना और प्रमुख उद्योग क्षेत्रों में परियोजनाओं को ऋण चुकाने के लिए लंबी अवधि यथा 25 वर्ष की अनुमति परियोजना के आर्थिक कार्यशील जीवन अथवा परियोजना की रियायत अवधि के आधार पर 5 वर्षों के आवधिक पुनर्वित्तपोषण के साथ होगी।
